

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में परिवारों की वित्तीय सहायता

270 श्री संवर लाल पंवार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कितने परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) उक्त सहायता राशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया है ; और

(ग) 1991-92 के वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस शीर्ष के अन्तर्गत राजस्थान को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार लाभग्राही उन्मुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत राजस्थान में 336400 परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले 3,87,487 अनुसूचित जनजाति परिवारों को सहायता दी गई ।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान 4712.28 लाख रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया गया ।

(ग) राजस्थान में परिवार लाभग्राही उन्मुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 1991-92 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता में आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित राशि 1613.36 लाख रुपये है जिसमें से 572.06 लाख रुपये पहली किस्त के रूप में निर्मुक्त किए जा चुके हैं ।

बेतवा नदी में पाया गया प्रदूषण

271 श्री राखव जो : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी, बेतवा में प्रदूषण का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त जांच के आधार पर पता लगाये गये प्रदूषण का स्तर कितना है तथा यह प्रदूषण किन-किन स्थानों पर है तथा प्रदूषण के मुख्य कारण क्या-क्या हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार बेतवा नदी में प्रदूषण को रोकने तथा इसकी सफाई करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, यदि हां, तो कब तक और कितनी मात्रा में सहायता देगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कमल नाथ) (क) और (ख) जी, हां । मंडीदीप, विदिशा और कुरवाई के साथ-साथ बेतवा नदी के कुछ हिस्से औद्योगिक बहिस्त्राव और घरेलू अपशिष्ट बहाये जाने के कारण अत्यन्त प्रदूषित हो गए हैं ।

(ग) और (घ) उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने और अपने बहिस्त्रावों का निर्धारित मानकों के अनुसार शोधन करने के निर्देश दे दिए गए हैं । मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के उपबंधों के तहत प्रमुख दोषी इकाइयों के विरुद्ध मुकदमे दायर किए हैं । सामूहिक बहिस्त्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए लघु इकाइयों के समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । जो उद्योग प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाते हैं उन्हें करों में रियायतों के जरिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है । जिन उद्योगों तथा नगरपालिकाओं में प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपकरण कार्य कर रहे हैं उन्हें पानी के उपयोग पर उपकरण में छूट दी जाती है । प्रदूषण को कम करने के उपकरण लगाने के लिए उद्योगों को ऋण की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ।